north-east and tribal areas as mentioned in the report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) At present there are no clear indications regarding the proposed tariff structure to be announced by the Telecom. Regulatory Authority of India.

Telephone Exchanges with STD facilities in Gujarat

46. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of Talukas and Panchayats in Gujarat having telephone exchanges with STD;

(b) the details of Talukas and Panchayats which do not have this facility and;

(c) the time by which STD facility will be provided in these Talukas and Panchayats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA):

(a) and (b) (i) All 184 Talukas are having Telephne Exchanges with STD facility.

(ii) There are 1294 Panchayat Exchanges, out of which 934 Exchanges have got STD facility.

(c) By March 2000, subject to availability of resources.

टेलीकॉम सॉफ्टवेयर पर आयात शुल्क

47. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के आयात पर शुल्क को कम करने से घरेलू उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है और भारी मात्रा में उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा कुल कितने संस्थानों के रुग्ण होने का अनुमान है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आयात शुल्क में कितनी कटौती की गयी है?

संचार मंत्रालय में संचार राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) (क) से (ग) सरकार ने 2.6.98 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 23/98 की क्रम सं॰ 207 के तहत दूरसंचार सॉफ्टवेयर के आयात पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क की अनुमति प्रदान की है, जबकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के आयात पर जीरो दर पर अनुमति प्रदान की गई थी तत्पश्चात् घरेलू उद्योग द्वारा मांग किए जाने पर सरकार ने 16.7.98 की अधिसूचना 43/98 के तहत दूरसंचार सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर की अनुमति प्रदान की। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जीरो दर तक सीमा-शुल्क में कटौती करने से घरेलू उद्योग पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। तथापि, औद्योगिक संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

Non-receipt of Bills by Subscribers

48. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the telephone subscribers of Habibpur Darin, Greater Noida, Gautambudh Nagar, are not getting their telephone bills regularly for the last one year, and

(b) if so, what action Government propose to take in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) Subscribers of village Habibpur are connected with the Telephone Exchange at Tilpatta. Bills of this telephone exchange are being sent regularly by post to subscribers. In additions, duplicate telephone bills can be obtained from the counter at Telephone Exchange, Sector-19, Telephone Exchange Sector-39, and The TRA Office, Godawari Complex, Sector-37.

सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता की राशि

49. **श्री कपिल सिब्बल:** क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर राजसहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वे मदें कौन-कौन सी हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राजसहायता की कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में दी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान दी जाने वाली राजसहायता की राशि की मात्रा का अनुमान लगाया है; यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। (नीचे देखिए)

(घ) सूचना केन्द्र सरकार के वर्ष 1999-2000 के बजट में दी जाएगी जो 27 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत किया जाना है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 1995-96	वास्तविक 1996-97	संशोधित 1997-98	बजट 1998-99
(क) मुख्य आर्थिक सहायता	12430	13664	18366	19883
1. खाद्य	5377	6066	7500	9000
2. चीनी	-	-	400	400
3. स्वदेशी (यूरिया) उर्वरक	4300	4743	6600	6000
4. आयातित (यूरिया) उर्वरक	1935	1163	826	983
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	318	20	440	500
6. किसानों को रिआयती दरों पर विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	500	1672	2600	3000
(ख) ब्याज आर्थिक सहायता	34	1257	78	39
(ग) अन्य आर्थिक सहायता	908	1204	1200	2103
कुल आर्थिक सहायता	13372	16125	19644	22025

CBI Enquiries into clearance of loans in Punjab National Bank

50. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the CBI has been examining clearance of loans of crores of rupees in the case of Punjab National Bank;

(b) if so, whether CBI has completed its inquiry into the matter and if so, the outcome thereof;

(c) whether such dubious methods have also been adopted in other public and private banks in the grant/sanction of loans which have gone into default; and

(d) if so, the details thereof and the action taken by RBI and CBI thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) The Central Bureau of Investigation (CBI) has reported that during the last 3 years i.e. 1996, 1997, 1998 and upto 31.1.1999, CBI has registered ten cases pertaining to grant of loans by Punjab National Bank. *Investigation* have been completed in four cases. Charge sheet has been filed in Court of law in one case. In two cases regular departmental action has been recommended and one case has been otherwise disposed off.

(c) and (d) CBI has reported that 71 such cases against other nationalised banks/ Cooperative banks have been registered during the above period and investigations have been completed in eight cases. Out of these, in five cases chargesheets have been filed, in one case regular departmental action has been recommended and two cases have been closed.

बजटीय घाटा

51. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: